शिमला से प्रकाशित

शैल समाचार

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailsamachar

वर्ष 48 अंक-50 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 18-25 दिसम्बर 2023 मूल्य पांच रूपये

भाजपा द्वारा याचिका वापस लेना मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी जीत

शिमला/शैल। भाजपा के एक दर्जन विधायकों ने उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

की नियुक्ति को चुनौती देने की याचिका प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की थी उसे अब इन विधायकों ने वापस ले लिया है। यह वापसी उस समय हुई है जब उच्च न्यायालय में इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व कर दिया गया था। लेकिन अब यह फैसला सुनाये जाने से पहले ही याचिका को वापस ले लिया गया। स्मरणीय है कि एन. के.शर्मा बनाम देवीलाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय उप-प्रधानमंत्री पद के मामले में फैसला देते हुये स्व.देवीलाल को राहत दे चुका है। हरियाणा में दुष्यन्त चौटाला के मामले में भी इसी तर्ज पर राहत दे चुका है। क्योंकि संविधान में उप-प्रधानमंत्री और उप-मुख्यमंत्री की एक जैसी ही स्थिति है। इसलिये यह तय माना जा रहा था कि मुकेश अग्निहोत्री को भी इस तर्ज पर राहत मिल जाएगी। ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में यह सवाल पूछा जाने लगा है कि भाजपा के एक दर्जन विधायकों ने उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी याचिका डाली ही क्यों थी। जबकि

✔ भाजपा की राजनीतिक नीयत और नीति बेनकाब
✔ इस जीत पर कांग्रेस की चुप्पी भी सवालों में

भाजपा शासित राज्यों में भी उप-मुख्यमंत्री नियुक्त हैं। अभी जिन राज्यों में भाजपा ने सरकारें बनायी है वहां भी उप-मुख्यमंत्री नियुक्त किये गये हैं। यह माना जा रहा था कि जब भाजपा के एक दर्जन विधायकों ने ऐसी याचिका डाली है तो निश्चित रूप से यह फैसला प्रदेश नेतृत्व की जगह पार्टी हाईकमान का ही रहा होगा। क्योंकि इसी के साथ मुख्य संसदीय सचिवों के खिलाफ भी याचिका डाली गयी थी और इसीलिये इसके कानूनी पक्ष पर कोई बड़ी चर्चा नहीं उठ पायी और जनता में सरकार के खिलाफ असवैधानिकता का संदेश भी चला गया। क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों के मामलों में कानूनी स्थिति अलग है। ऐसे में यह माना जा रहा था कि उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ यह याचिका डालकर भाजपा प्रदेश को राजनीतिक तौर पर अस्थिर करना चाहती थी जो सफल नहीं हो पायी। उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ याचिका को वापस लिया जाना सरकार और कांग्रेस की एक बड़ी जीत है। इससे भाजपा की राजनीतिक नीयत और नीति दोनों का खुलासा हो जाता है। परन्तु इस जीत पर कांग्रेस और सरकार की ओर से भाजपा के खिलाफ बड़ी आक्रामकता का सामने न आ पाना भी कांग्रेस के अन्दर की स्थिति को ब्यान कर जाती है।

किसी के भी खिलाफ स्थायी गैग आदेश नहीं लगाया जा सकता

देवाशीष भट्टाचार्य बनाम रचना गुप्ता मामले में उच्च न्यायालय ने किया स्पष्ट कोई भी लेखन असत्य और अप्रमाणित नहीं होना चाहिये

शिमला/शैल। क्या कोई व्यक्ति आर.टी.आई. के माध्यम से उसके बारे में जुटाई गयी जानकारी के सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया मंच पर सार्वजनिक होने से बदनाम हो सकता है? क्या ऐसे आर.टी.आई. एक्टिविस्ट के खिलाफ कोई अदालत यह स्थाई प्रतिबन्ध लगा सकती है कि अमुक व्यक्ति किसी अमुक व्यक्ति या उसके परिजनों के खिलाफ सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में "Any statment of any nature" नहीं लिख सकता है। यह सारे सवाल आर. टी.आई. एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य बनाम रचना गुप्ता मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय में चर्चा में आये हैं। उच्च न्यायालय ने ऐसे आदेश को 12-12-2023 को संशोधित करते हुये स्पष्ट किया है कि ऐसा स्थायी गैग आदेश कानून सम्मत नहीं है उच्च न्यायालय ने पुराने आदेश को संशोधित करते हुये कहा है कि देवाशीष अपने लेखन के लिये स्वतंत्र है। बशर्त कि ऐसा लेखन असत्य और अप्रमाणित न हो। स्मरणीय है कि 2019 में लोक सेवा आयोग की सदस्य डॉ. रचना गुप्ता ने देवाशीष भट्टाचार्य के खिलाफ एक करोड़ की मानहानि का मुकद्दमा दायर किया था जो अब तक लंबित है। लेकिन 2020

शेष पृष्ठ 8 पर.............

मुख्यमंत्री ने 47.36 करोड़ से निर्मित संजौली-ढली सुरंग का उद्घाटन किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 47.36 करोड़ रुपये से निर्मित 154.22 मीटर लंबी संजौली-ढली सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग मौजूदा ढली टनल के सामानांतर बनाई गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में इस सुरंग का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा था लेकिन वर्तमान सरकार ने निर्माण कार्य में तेजी लाई और एक साल के भीतर इस सुरंग को तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि विकास कार्यों से जुड़ी परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि प्रदेश के लोगों को परियोजनाओं से जुड़े लाभ जल्द से जल्द प्रदान किए जाएं।

पुरानी ढली टनल वर्ष 1852 में बनाई गई थी जिससे कि एक समय में एक तरफा ट्रैफिक का संचालन ही संभव था, जिस कारण यहां ट्रैफिक की समस्या रहती थी। नई टनल के संचालन से ट्रैफिक की समस्या समाप्त होगी और स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को निर्बाध यातायात सुविधा प्राप्त होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हिमाचल की आर्थिकी के लिए महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है और बेहतर यातायात सुविधाओं के निरन्तर विकास से इस क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सुरंग शिमला के मुख्य पर्यटन गतंव्य स्थलों, जैसे कि कुफरी, नालदेहरा, तत्तापानी, नारकंडा और चायल, पर यातायात सुगम बनाएगी। शिमला शहर के लिए यह सुरंग सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिक पर्यटन अधोसंरचना का विकास कर पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय लोगों की जरूरतों को भी पूरा कर रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नई सुरंग के निर्माण से शिमला शहर के सर्कुलर रोड पर ट्रैफिक की समस्या का व्यवहारिक और स्थाई समाधान होगा। इस परियोजना से स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी सुरंग का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा।

रक्तदान मानव सेवा की उत्कृष्ट मिसाल:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रेडक्रॉस भवन, शिमला में लायंस क्लब शिमला के सहयोग से राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया।

राज्यपाल ने रक्तदाताओं के साथ संवाद करते हुए परोपकारी कार्य के लिए उनकी निःस्वार्थ सेवा की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य रेडक्रॉस अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से आम जनता में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ ऐसे शिविरों के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि रक्तदान मानव सेवा की उत्कृष्ट मिसाल है।

इस अवसर पर राज्यपाल ने रक्तदाता प्रमाण पत्र भी प्रदान किये।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा, नगर निगम शिमला की पूर्व महापौर कुसुम सदरेट और लायंस क्लब शिमला के अध्यक्ष विकास सेठ उपस्थित थे।

चौथी बार सीसीटीएनएस में पहला स्थान हासिल करने पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की सराहना की

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने वर्ष 2023 के लिए अपराध और आपराधिक नेटवर्क ट्रैकिंग और सिस्टम सीसीटीएनएस प्रदर्शन में पहला स्थान हासिल किया है। गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में 21 दिसंबर, 2023 से आयोजित दो दिवसीय गुड प्रेक्टिसीज सीसीटीएनएस/आईसीजेएस के वार्षिक सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश पुलिस को सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए पुलिस विभाग को बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में सीसीटीएनएस प्रदर्शन में लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश पुलिस ने सीसीटीएनएस प्रदर्शन में कई राज्यों से आगे बढ़कर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल वरिष्ठ अधिकारियों के कुशल मार्गदर्शन में एससीआरबी के अन्तर्गत सभी क्षेत्र स्तरीय पुलिस अधिकारियों और राज्य स्तरीय सीसीटीएनएस टीम के समर्पित और सामूहिक प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल की है।

पुलिस महानिदेशक, संजय कुंडु ने पुलिस विभाग की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में उनकी निरंतर प्रेरणा और मदद के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देश के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सीसीटीएनएस परियोजना कार्यान्वयन प्रदर्शन की निगरानी के लिए भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो एनसीआरबी, नई दिल्ली ने पूर्वनिर्धारित पैरामीटर के आधार पर राज्यवार सीसीटीएनएस प्रदर्शन रैंकिंग तय की है। हिमाचल प्रदेश ने सीसीटीएनएस परियोजना संबंधी राज्य के सभी मानकों को पूर्ण करते हुए इसका सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया है।

उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस भारत में पुलिस कार्यप्रणाली की रीढ़ है और हिमाचल प्रदेश पुलिस इसमें वर्ष 2020, 2021 और 2022 के समान इस वर्ष भी शीर्ष स्थान पर रही है।

जाइका वानिकी परियोजनाओं की ड्रोन से होगी निगरानी

शिमला/शैल। जाइका वानिकी परियोजना हाईटैक हो चुकी है। परियोजना के तहत होने वाली सभी गतिविधियों पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पौधरोपण, जंगलों में आग लगने की घटना समेत प्रोजेक्ट के अंतर्गत हो रहे हरेक कार्यों को ड्रोन के माध्यम से कड़ी नजरें रखी जाएंगी। जाइका वानिकी परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर जीआईएस रजनीश कुमार के नेतृत्व मे रोहड़ू वन मंडल के सरस्वतीनगर वन परिक्षेत्र में ड्रोन से सर्वे किया गया। रजनीश कुमार ने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना के तहत किए गए कार्यों को ड्रोन में कैद किया जा रहा है। इसके साथ-साथ जंगलों में आग लगने की घटना का भी पता लगा सकते हैं कि आग लगने से वन संपत्तियों के नुकसान का रियल टाइम और आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंचने के लिए क्या कुछ इंतजमाम होने चाहिए। रजनीश कुमार ने कहा कि सभी ग्राम वन विकास सामितियों के दायरे में हुए कार्यों को ड्रोन के माध्यम से कैद किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाइका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया के दिशा-निर्देशानुसार आने वाले दिनों में राज्य के अन्य ऐसे क्षेत्रों में ड्रोन तकनीक से प्रोजेक्ट के कार्यों की स्टीक प्लालिंग की जाएगी।

हिम महोत्सव में 5 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान

दिल्ली हाट में हिमक्राफ्ट उत्पादों एवं हिमाचली व्यंजनों की भारी मांग

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली हाट में 30 दिसम्बर 2023 तक आयोजित होने वाले 'हिम महोत्सव' में हिमक्राफ्ट उत्पादों व हिमाचली व्यंजनों की भारी मांग है। इसके अंतर्गत हिमक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम तथा कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रदेश के कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों की बिक्री के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध करवाया गया है।

हिमक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक जतिन लाल ने बताया कि दिल्ली में प्रदेश के हस्तशिल्प, हथकरघा, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों को काफी सराहा जा रहा है। पहले 3 दिनों में ही लगभग 40 लाख रुपए की बिक्री का अनुमान है। दूसरे और तीसरे दिन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों सहित विदेशी मेहमानों ने भी यहां जमकर खरीदारी की। उन्होंने बताया कि क्रिसमस और नववर्ष को देखते हुए विभाग को 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार का अनुमान है।

हिम महोत्सव में कुल्लू और किन्नौरी शॉल, लाहौली मोजे और दस्ताने, चमड़े पर जरी और रेशम के धागे से महीन कारीगरी से तैयार चंबा चप्पल और धातु शिल्प का कमाल चंबा थाल, कांगड़ा पेंटिंग तथा कांगड़ा चाय और बांस व शिल्प उत्पाद, भेड़ ऊन, अंगोरा, पश्मीना, याक ऊन की हाथ से बुनी गई शॉल, सिरमौरी लोईया और स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए अचार और जैम सहित हिमाचली व्यंजनों में कांगड़ा, चम्बा और मंडयाली धाम मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।

दिल्ली हाट में विभाग द्वारा हिमक्राफ्ट के 35, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रदेश के 20 स्वयं सहायता समूहों, हिमकोस्टे के 5 और हिमाचली व्यंजनों की बिक्री के लिए 5 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं।

विभाग द्वारा दिल्ली एनसीआर के लोगों को आकर्षित करने के लिए हिमाचल के विभिन्न जिलों के लोक नृत्यों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस तरह हिम महोत्सव में कारीगरों, बुनकरों, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों और हिमाचली व्यंजनों के साथ-साथ हिमाचल की लोक संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य प्रदेश की अनूठी कला, संस्कृति और व्यंजनों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित कर इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाना है। हिम महोत्सव के माध्यम से प्रदेश के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों से लोगों को रूबरू करवाया जा रहा है जिससे बड़े महानगरों से भी इन उत्पादों के ऑर्डर प्राप्त हो सकें। कारीगरों की व्यावसायिक गतिविधियों को विस्तार मिलने के साथ-साथ इससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

हिमाचल पुलिस का पर्यटकों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह

शिमला/शैल। क्रिसमस से एक दिन पहले 65,000 पर्यटकों के साथ 12,000 वाहनों ने रोहतांग सुरंग को पार किया। अटल टनल रोहतांग के माध्यम से प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को कुल्लू और लाहौल स्पीति पुलिस से बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल रहा है, जिससे यात्री सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित कर रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक लाहौल एवं स्पिति मयंक चौधरी स्वयं पुलिस अधिकारियों और पर्यटकों की सक्रिय रूप से निगरानी करके उन्हें निर्देशित कर रहे हैं। लाहौल एवं स्पीति और कुल्लू जिले के पुलिस कर्मियों ने -12 डिग्री तापमान में भी पर्यटकों को बहुत ही पेशेवर तरीके से सम्भाल कर उनका मार्ग दर्शन कर रहे हैं। चुनौतीपूर्ण-12 डिग्री सेल्सियस तापमान के बावजूद, पुलिस बल चौबीसों घंटे अथक परिश्रम कर रहा है।

हिमाचल प्रदेश पुलिस का पर्यटकों से आग्रह है कि वह स्थानीय प्रशासन और मौके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के दिशा-निर्देशों व यातायात नियमों की पालना करके सुरक्षित व आरामदायक यात्रा का आन्नद लें।

सरकार धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध

शिमला/शैल। ऊना जिले में माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर तक यात्री रोप-वे के विकास के लिए रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हिमाचल प्रदेश के निदेशक अजय शर्मा ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में मैसर्स स्काई हिमालय रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अमिताभ शर्मा को लेटर ऑफ अवार्ड कार्य पत्र प्रदान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 1.1 किलोमीटर लंबे इस हवाई रोपवे का निर्माण 76.50 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा। इस अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली से दोनों ओर प्रति घण्टा 700 यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित होगी। साथ ही, यहां आने वाले पर्यटकों व श्रद्धालुओं को एक नया यात्रा अनुभव भी होगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य के युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी और धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व है। हिमाचल प्रदेश स्थित शक्तिपीठों में इसका प्रमुख स्थान है।

उन्होंने कहा कि माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में रोप-वे सुविधा से न केवल भीड़भाड़ से राहत मिलेगी बल्कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षित और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार तीर्थयात्रियों के लिए यादगार अनुभव और सुविधा प्रदान करने के लिए धार्मिक स्थानों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए विशेष अधिमान दे रही है।

उन्होंने मैसर्स स्काई हिमालय रोपवेज प्राइवेट लिमिटेड को इस परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को अतिशीघ्र बेहतर सुविधा मिल सके।

शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल का आयोजन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला विंटर कार्निवल का शुभारंभ करते हुए कहा कि शिमला में विंटर कार्निवल का आयोजन पहली बार किया जा रहा है और इससे शहर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि शिमला विंटर कार्निवल 5 जनवरी तक चलेगा तथा इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक परेड को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान लगभग 450 महिलाओं ने महानाटी प्रस्तुत की, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल रहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले एक दो दिन में हिमाचल प्रदेश में 30 हजार पर्यटक वाहन आये हैं जो कि प्रदेश में पर्यटन उद्योग के एक बार फिर से खड़ा होने के अच्छे संकेत हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र का हिमाचल की आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान है तथा प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन क्षेत्र के लिए पूर्व के 50 करोड़ बजट के स्थान पर वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 3 हजार करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों का स्वागत अतिथि देव भव: की परम्परा के अनुरूप किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य के सभी रेस्तरां तथा ढाबों सहित खाने की अन्य दुकानों को 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक चौबिसों घंटे खुला रखने की छूट दी है।

मुख्यमंत्री ने रिज पर लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें जिला प्रशासन शिमला सहित विभिन्न विभागों ने स्टॉल स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री का कार्निवल में पहुंचने पर पारंपरिक लोक गीत-संगीत के बीच स्वागत किया गया।

इस अवसर पर विधायक हरीश जनारथा ने शिमला विंटर कार्निवल के पहले आयोजन पर सभी संबंधित अधिकारियों और नगर निगम शिमला को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश में रेस्तरां व ढाबों को 24 घंटे खुला रखने के निर्णय से पर्यटकों के साथ-साथ पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों को लाभ मिलेगा।

इससे पूर्व, नगर निगम शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन राज्य सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसमें राज्य की लोक संस्कृति पर्यटकों के सामने प्रस्तुत की जाएगी।

पांच जनवरी तक चलने वाले शिमला विंटर कार्निवल में हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति के प्रदर्शन के साथ-साथ देसी पकवानों के स्टॉल भी लगाये गये हैं। इसके साथ-साथ इस आयोजन के दौरान लेज़र शो भी प्रस्तुत किया गया।

आईटी पार्क चैतड़ू का कार्य एक वर्ष में पूरा करने के निर्देश:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के चैतड़ू में लगभग 17 करोड़ रुपए की लागत से दो एकड़ भूमि पर निर्माणाधीन आईटी पार्क का औचक निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 100 कंपनियों ने इस पार्क में अपने कार्यालय स्थापित करने में रुचि दिखाई है तथा कंपनियों को प्लग एंड प्ले आधार पर काम करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि आईटी पार्क के निर्माण से स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार कांगड़ा जिला को आईटी हब के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रही है, ताकि राज्य के विकास को गति मिल सके।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा वर्ष 2024 तक आईटी पार्क का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला प्रशासन कांगड़ा को यहां सड़क, बिजली व पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर प्रदान करने को कहा, ताकि यहां आने वाली कंपनियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

गोकुल बुटेल ने मुख्यमंत्री को निर्माणाधीन आईटी पार्क के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

'प्रॉसिक्यूशन पिलर' के सफल कार्यान्वयन में हिमाचल को दूसरा स्थान

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आईसीजेएस परियोजना 'प्रॉसिक्यूशन पिलर' के सफल कार्यान्वयन में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल करने पर राज्य के अभियोजन विभाग को बधाई दी। विभाग को हाल ही में दिल्ली में अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम/आईसीजेएस में 'गुड प्रेक्टिसिज़' पर आयोजित 5वें सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की गरिमामय उपस्थिति में गृह सचिव अभिषेक जैन और अभियोजन विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया।

इस अवसर पर अभिषेक जैन ने मुख्यमंत्री को आईसीजेएस कार्यक्रम और अखिल भारतीय ई-प्रोसिक्यूशन पोर्टल के संबंध में जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि विभाग भविष्य में भी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा ताकि गरीबों और जरूरतमंदों को शीघ्र न्याय दिलाया जा सके।

राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना के लिए मानक संचालन प्रणाली अधिसूचित

शिमला/शैल। परिवहन विभाग ने राज्य के बेरोज़गार युवाओं को परिवहन क्षेत्र में रोज़गार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत विस्तृत मानक संचालन प्रणाली अधिसूचित की है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डों व अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबन्ध के आधार पर लगाई जानी है।

इस योजना का लाभ अधिक से अधिक बेरोज़गार युवाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने ई-टैक्सी के आवेदन करने की आवश्यक योग्यता का पुन:निर्धारण किया है, जिसके अनुसार आवेदक यदि किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 10वीं पास हो तो उसके पास वाहन चलाने का 7 साल का अनुभव होना चाहिए। यदि आवेदक 10वीं पास नहीं है तो उसके पास वाहन चलाने का 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य है।

इस योजना के अन्तर्गत आवेदक 5 जनवरी, 2024 तक परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

हिमाचल प्रदेश को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को देशभर में सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदेश को यह पुरस्कार एग्रीकलचर टुडे ग्रुप द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 14वें एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉनक्लेव-2023 के अवसर पर प्रदान किया। प्रदेश की ओर से यह पुरस्कार बागवानी सचिव सी. पॉलरासु ने प्राप्त किया।

बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य का पुरस्कार प्राप्त होने पर राज्य के किसानों और बागवानों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में राज्य में उच्च घनत्व बागवानी पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रदेश में कम बागवानी वाले क्षेत्रों में बागवानी के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। इससे युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर सृजित करने के साथ-साथ क्षेत्र की बागवानी भी सुदृढ़ हो रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बागवानी विकास रणनीति तथा नियोजन कार्य योजना 2023-2032 तैयार की गई है ताकि आवश्यकता के अनुसार अवसंरचनाओं और ढांचागत सुविधाओं का सृजन किया जा सके।

गन्दम की भण्डारण सीमा घटाई गई

अतिरिक्त स्टॉक का 8 जनवरी तक निपटारा करने के निर्देश

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने गन्दम के थोक व्यापारियों के लिए भण्डारण की सीमा पुन:निर्धारित की है। केन्द्र सरकार द्वारा थोक व्यापारियों द्वारा एक समय में भण्डारण किये जाने वाले गन्दम की सीमा घटा दी गई है। पहले थोक व्यापारी 2000 मीट्रिक टन गन्दम का भण्डारण कर सकता था, लेकिन अब यह स्टॉक सीमा 1000 मीट्रिक टन कर दी गई है। प्रत्येक रिटेल विक्रेता अब 5 मीट्रिक टन तक गन्दम अपने स्टॉक में रख सकेगा, जबकि पहले यह सीमा 10 मीट्रिक टन थी। इसी तरह बिग चेन रिटेलर एक डिपो पर 10 मीट्रिक टन के स्थान पर 5 मीट्रिक टन गन्दम का ही भण्डारण कर सकेगा।

विभाग की ओर से सभी व्यापारियों को उनके पास रखे गये अतिरिक्त स्टॉक का 8 जनवरी, 2024 तक निपटारा करने के निर्देश दिए गये हैं। साथ ही सभी व्यापारियों से यह भी आग्रह किया है कि वे संशोधित स्टॉक सीमा से ज्यादा गन्दम अपने स्टॉक में न रखें।

विभाग की ओर से सभी जिला नियन्त्रकों और निरीक्षकों को भी गन्दम के थोक व्यापारियों तथा रिटेलरों को नियमित रूप से चौक करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यापारी अथवा रिटेलर निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक गन्दम का भण्डारण करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कारवाई अमल में लाई जाएगी।

सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है–वह पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगता। पूर्ण रूप से नि:स्वार्थ व्यक्ति, सबसे सफल हैं।

...... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

कांग्रेस को आत्म चिन्तन करना होगा

तीन राज्यों में कांग्रेस को मिली अप्रत्याशित हार के कारणों को कोई आधिकारिक खुलासा अभी तक सामने नहीं आया है। यह हार कांग्रेस ही नहीं बल्कि आम आदमी के लिये भी अप्रत्याशित रही है। इस हार के बाद कांग्रेस ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव करते हुये कुछ राज्यों के प्रभारीयों में बदलाव किया है। कांग्रेस की हार का पूरे देश पर प्रभाव पड़ा है। इस नाते इस पर चिन्तन करने का अधिकार और कर्तव्य हर नागरिक का हो जाता है। देश में सत्ता परिवर्तन 2014 में अन्ना आंदोलन से हुआ यह स्पष्ट है। इस आंदोलन में कांग्रेस के दस वर्ष के शासनकाल को भ्रष्टाचार का पर्याय घोषित प्रचारित किया गया। लोकपाल की नियुक्ति मुख्य मांग बनी 2014 के चुनाव में काले धन की वापसी और कुछ अन्य लुभावने वायदे परोसे गये। और सत्ता परिवर्तन हो गया। उसके बाद 2019 के चुनाव में नोटबंदी के फायदे, आतंकवाद का खात्मा, धारा 370 और तीन तलाक खत्म करना आदि नये चुनावी मुद्दे बन गये। अब 2024 के चुनाव में 370 हटाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर और राम मंदिर का उद्घाटन नये मुद्दे तैयार हो गये है। लेकिन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करना देश के आर्थिक संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से निजी क्षेत्र को सौंपना बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे आम आदमी को प्रभावित करने वाले मुद्दे गौण होते जा रहे हैं । ऐसे दर्जनों मुद्दे हैं जो आम आदमी को सीधे प्रभावित करते हैं।

सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे होने के बावजूद भी सत्ता पक्ष का पहले से ज्यादा ताकतवर होकर हर चुनाव में निकलना अपने में ही कई सवाल खड़े करता है । यह सबसे चिनतनीय विषय हो जाता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। सत्ता पक्ष हर चुनाव में परोक्ष अपरोक्ष रूप से मुफ्ती के नये नये वायदे लेकर चुनाव में आता है और विपक्ष भी उसी तर्ज पर मुफ्ती के वायदे लेकर आज आने लग गया है। हिमाचल में कांग्रेस की दस गारटीयां भाजपा पर भारी पड़ी और उसे सत्ता मिल गयी लेकिन यही गारटीयां पूरी न हो पाना इन राज्यों के चुनाव में हार का एक बड़ा कारण भी बनी। अब रिजर्व बैंक ने जिस तरह से राज्यों को ओ.पी.एस. पर चेतावनी दी है उससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस या कोई भी दूसरा विपक्षी दल इस दिशा में मोदी सरकार का मुकाबला नहीं कर सकता ऐसे में मुफ्ती के वायदों के सहारे मोदी से सत्ता छीन पाना संभव नहीं होगा।

इस समय मोदी सरकार के खिलाफ इतने मुद्दे हैं जिन पर यदि देश को जागृत किया जाये तो इस सरकार को हराना कठिन नहीं है लेकिन क्या कांग्रेस इन मुद्दे को सूचीबद्ध करके अपने ही कार्यकर्ताओं को इस लड़ाई के लिए तैयार कर पा रही है शायद नहीं। कांग्रेस के ही पदाधिकारीयों को यह ज्ञान नहीं है कि 2014 से लेकर आज तक मोदी सरकार ने देश के सामने क्या-क्या परोसा और उनसे कितना पूरा हुआ। हर चुनाव के बाद ईवीएम पर सवाल उठे हैं और इन सवालों की शुरुआत एक समय भाजपा नेतृत्व में ही की है। आज ई.वी.एम. पर उठते सवालों का आकार और प्रकार दोनों बढ़ गये है। आम आदमी भी अब सवाल उठाने लग पड़ा है। ऐसे में यदि एक जन आंदोलन ई.वी.एम. हटाने से लेकर देश में खड़ा हो जाये और यह कह दिया जाये कि ई.वी.एम. के रहते चुनाव में हिस्सा नहीं लिया जायेगा। एक चुनाव विपक्ष की भागीदारी के बिना ही होने दिया जाने के हालात पैदा कर दिये जाये तो शायद सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयोग दोनों ही कुछ सोचने पर विवश हो जाये इसी के साथ कांग्रेस ने जिस तरह से संगठन में फेरबदल किया है उसी तर्ज पर जहां उसकी सरकारें हैं वहीं पर उसे ऑपरेशन करने होंगे।

एक घोषित आतंकी समूह का समर्थन फिलिस्तीनी जनता के साथ धोखा

गौतम चौधरी

एक व्यक्ति जिसके पास बेसुमार ताकत है लेकिन वह परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार व चिंतन में लचीलापन नहीं लाता, ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में टूट जाता है, ऐसे व्यक्ति की सफलता में सदा संदेह बना रहता है क्योंकि ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में समझौतों का समावेश नहीं करता है। वहीं दूसरा व्यक्ति काल और परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार व चिंतन में समझौतों को समावेश करता है तथा व्यवहार में लचीलापन रखता है। ऐसे व्यक्ति की सफलता में कहीं कोई संदेह नहीं होता है। अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने में वह कामयाब होता है। इसकी व्याख्या करें तो इसे वीरतापूर्ण लचीलापन कहा जा सकता है। इस मामले में इमाम हसन की शांति संधि सबसे शानदार और ऐतिहासिक उदाहरण है।

मध्य-पूर्व में लंबे समय से अशांति बनी हुई है। इसका कारण इजरायल-फिलिस्तीन के बीच संघर्ष है। अभी हाल ही में हमास के एक तरफा आक्रमण के बाद एक बार फिर-से संघर्ष तेज हो गया है। इस संघर्ष ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। इस मामले में दुनिया के कई देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। भारत हमेशा-से फिलिस्तीन के प्रति अपना समर्थन दिखाता रहा है। इस बार के संघर्ष में भी भारत ने अपने पारंपरिक विदेश नीति के अनुसार ही व्यवहार किया और फिलिस्तीन की आम जनता के लिए संघर्ष को तत्काल रोकने की वकालत की। भारत बहुसांस्कृतिक देश है, इसलिए भारत को अपनी आंतरिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विदेशी व्यवहार को सिरे चढ़ाना होता है। भारत के द्वारा फिलिस्तीनी जनता के प्रति सदसयता ने कई सवालों को जन्म दिया है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि भारतीय मुसलमानों को गाजा पट्टी के प्रभारी समूह हमास के बारे में किस प्रकार का नजरिया रखना चाहिए? यह सवाल तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा आयोजित रैली को हमास के नेता आभासी माध्यम से संबोधित करते हैं।

यह ध्यान में रहे कि फिलिस्तीन के लिए भारत का समर्थन वहां की आम जनता के लिए न्याय, आत्मनिर्णय और दो-राज्य समाधान के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए है। भारत दुनिया का पहला देश है, जिसने फिलिस्तीन को 1988 से एक देश के तौर पर आधिकारिक रूप से मान्यता दे रखा है। यही नहीं भारत फिलिस्तीनी जनता के लिए सदा से अपनी चिंता जताता रहा है। भारतीय कूटनीतिकों ने संयुक्त राष्ट्र के साथ ही दुनिया के अन्य कई मंचों से फिलिस्तीनी प्रस्तावों का समर्थन किया है। समय समय पर भारत ने फिलिस्तीनी लोगों को वित्तीय और मानवीय मदद भी पहुंचाई है। अभी हाल के संघर्ष में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से मानवीय सहायता फिलिस्तीन तक पहुंचाई है। फिलिस्तीनी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और उसके व्यक्तित्व का विकास, भारतीय वैदेशिक कूटनीति का अंग है।

गाजा में हमास के शासन के दौरान फिलिस्तीनी राजनीति साफ तौर पर विभाजित दिख रहे हैं। फिलिस्तीनी गुटों में संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। यह हिंसक भी हो रहा है। ऐसे में फिलिस्तीन के अंदर राजनीतिक एकता एक बड़ी चुनौती है। यह सफल शांति वार्ता का महत्वपूर्ण पहलू है। एक सर्वमान्य अवधारणा है कि किसी एक गुट का समर्थन करना अलोकतात्रिक है। एक खास गुट का समर्थन, वैधानिक लोकतंत्र और स्वशासन के बुनियादी सिद्धांतों को नष्ट कर देती है। दूसरी ओर, कई शांति पहलों को खारिज करने के अलावा, हमास ने इजरायल के अस्तित्व को ही खारिज कर दिया है। शांति पहल को विफल करने वाले संगठन का समर्थन कर स्थायी शांति की कल्पना नहीं की जा सकती है। हमास लगातार शांति समझौतों को खारिज करता रहा है। ऐसे में हमास को प्रोत्साहित करने से क्षेत्रीय स्थिरता बिगड़ सकती है और हिंसा की संभावना बढ़ जाएगी।

यहां हमें यह भी समझना होगा कि जब हमास जैसे गैर-राज्य तत्व, जिसकी वैश्विक मान्यता न हो, संघर्ष क्षेत्र में प्रवेश करता है तो आम जनता ही परेशान होती है। हमास जैसे संगठनों को यह समझना होगा कि यह दो गुटों के बीच संघर्ष के बजाय विशुद्ध रूप से मानवाधिकारों की लड़ाई है। यह जरूरी है कि मुसलमान और वैश्विक समुदाय हमास जैसे समूहों का समर्थन करते वक्त इस बात का ख्याल रखें। चूंकि भारत सरकार फिलिस्तीनी लोगों की स्थिति के प्रति सहानुभूति रखती है, इसलिए भारतीयों, विशेषकर मुसलमानों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित हमास मिलिशिया के साथ जुड़ने के बजाये राजनयिक और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा दें। यह किसी को नहीं भूलना चाहिए कि फिलिस्तीन-इजरायल संघर्ष का एक मात्र समाधान शांतिपूर्ण समझौता ही है, जिसमें दोनों देशों को दोनों देशों के अस्तित्व स्वीकारना होगा। इजरायल यदि यह सोच रहा होगा कि हम फिलिस्तीन को मिटा देंगे, ऐसा संभव नहीं है। वहीं हमास या उग्रपंथी इस्लामिक चिंतक यदि यह समझ रहे होंगे कि इजरायल को यहां से खदेड़ दिया जाएगा तो फिलहाल यह भी संभव नहीं है। इसलिए दोनों पक्षों को लचीला व्यवहार तो अपनाना ही होगा।

नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए की गयी पहलें

शिमला। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए अनेक पहलें की हैं। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि स्कूलों के उन्नयन के लिए पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, कुल 6448 स्कूलों का चयन किया गया और पहली किस्त के रूप में केवीएस /एनवीएस के साथ 27 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 6207 पीएम श्री स्कूलों को 630.11 करोड़ रुपये जारी किए गये। समझ और संख्यात्मकता के साथ पढ़ने में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, निपुण भारत, विद्या-प्रवेश-स्कूल तैयारी मॉडयूल, डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा के लिए पीएम ई-विद्या, दीक्षा (ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल अवसंरचना) वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में, मूलभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठयचर्या संरचना (एनसीएफ एफएस), 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जदुई पिटारा, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठयचर्या संरचना, स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) 1.0, 2.0 और 3.0 स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, 1500+ माइक्रो पाठयक्रमों, 5 बिलियन+ लर्निंग सत्रों, 12 बिलियन+ क्यूआर कोड, 20,000 हजार+ इकोसिस्टम प्रतिभागियों, विभिन्न लिंक्ड बिल्डिंग ब्लॉकों में चल रहे 15,000+ सूक्ष्म सुधारों के साथ एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला (एनडीईएआर), न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम या यूएलएएस आदि, जो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी निरक्षरों को लक्षित करता है।

समग्र शिक्षा योजना को एनईपी 2020 की सिफारिश के साथ पूरी तरह से संरेखित किया गया है, जिसमें 2,94,283.04 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय परिव्यय शामिल है, जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा है। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना को भी एनईपी 2020 की सिफारिश के साथ जोड़ा गया है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना मानदंडों, मानकों, दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने और छात्र मूल्यांकन से संबंधित गतिविधियों को लागू करने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की गई है।

स्कूली बस्तों के भार को कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली बस्तों के वजन संबंधी नई नीति राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में संचारित की गई है।

चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए आईआईटी, एनआईटी, आरआईई, इग्नू और सरकारी कॉलेजों सहित 42 संस्थानों को मान्यता प्रदान गई है।

उत्कृष्ट पेशेवरों का एक बड़ा पूल बनाने के लिए राष्ट्रीय मेंटरिंग मिशन (एनएमएम) भी शुरू किया गया है, जो स्कूली शिक्षकों को सलाह देने के इच्छुक हैं। एनएमएम को 30 केंद्रीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। इसके अलावा, पूरे देश में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को मजबूत करने के लिए विद्यांजलि नामक एक स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब तक 6,71,512 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों ने विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण किया है और 4,43,539 स्वयंसेवकों ने अपना पंजीकरण करवाया है।

उच्च शिक्षा में, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न पहल/सुधार किए गए हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ), नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी), मल्टीपल आगमन/ प्रस्थान आदि शुरू किए गए हैं। अब तक एबीसी पोर्टल पर 1,667 विश्वविद्यालय/ आईएनआई / एचईआई शामिल हुये हैं और 2.75 करोड़ छात्र पंजीकृत हैं। समानता और समावेश के साथ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय भाषाओं में पाठयक्रम शुरू किए जा रहे हैं। जेईई, एनईईटी, सीयूटीईटी जैसी प्रवेश परीक्षाएं 13 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। 12 भारतीय भाषाओं में विभिन्न विषयों पर यूजी छात्रों के लिए 100 किताबें शुरू की गई है। और प्रथम वर्ष की 20 तकनीकी पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, वर्तमान में 95 उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) दवारा 1149 ओडीएल कार्यक्रमों चलाये जा रहे हैं और 66 उच्च शिक्षा संस्थान 371 ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश कर रहे हैं। 19 लाख से ज्यादा छात्र इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने और लचीलापन प्रदान करने के लिए, लगभग 295 विश्वविद्यालयों ने 'स्वयं' कार्यक्रम को अपनाया है जो शिक्षार्थियों को 'स्वयं' मंच से 40% तक क्रेडिट पाठयक्रमों का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करता है। 9 लाख से ज्यादा छात्र प्रति वर्ष प्रॉक्टेड परीक्षा के माध्यम से स्वयं प्रमाणपत्र प्राप्त करते हैं। इन प्रमाणपत्रों का उपयोग उस विश्वविद्यालय द्वारा क्रेडिट हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है जिसमें छात्र नामांकित है। उच्च शिक्षण संस्थानों में नामांकन से लेकर डिग्री प्रदान करने तक के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) आधारित समाधान (एसएएमटीएच) का 32 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए लगभग 2700 विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। 7 राज्यों के उच्च शिक्षा विभाग भी चालू हैं। 7 राज्य उच्च शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल हैं।

उद्योग और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाठयक्रम एवं पाठयक्रम विकसित करने में उद्योग जगत के विशेषज्ञों के साथ काम करने के लिए एचईआई को सक्षम बनाने के लिए पहल की गई है जैसे कि प्रैक्टिस के प्रोफेसर पर दिशानिर्देश, सिस्को/ आईबीएम/ मेटा/ एडोब/ माइक्रोसॉफ्ट/ सेल्स फोर्स आदि के साथ उद्योग-संरेखित पाठयक्रम निर्माण करने के लिए समझौता ज्ञापन, उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप अंतर्निहित डिग्री प्रोग्राम की पेशकश, लगभग 10560 एचईआई के कुल पंजीकरण के साथ इंटर्नशिप के लिए एकल एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल और अब तक 73383 उद्योगों को शामिल किया गया है। अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, लगभग 7568 संस्थानों की नवाचार परिषदों और लगभग 104 विचार विकास, मूल्यांकन और अनुप्रयोग प्रयोगशालाओं (आईडीईए) की स्थापना की गई है।

अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए, भारत में विदेशी उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन पर अधिनियम जारी किए गए हैं। इसके अलावा, जांजीबार, तंजानिया में आईआईटी मद्रास और अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के परिसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तंजानिया के जंजीबार -तंजानिया स्थित आईआईटी मद्रास कैंपस में कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) पर संकाय का प्रशिक्षण/ उन्मुखीकरण, उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में रहने वाले कलाकारों/ कारीगरों को सूचीबद्ध करने, भारतीय विरासत एवं संस्कृति पर आधारित पाठयक्रमों की शुरुआत करने, उच्चतर शिक्षा पाठयचर्या में भारतीय ज्ञान को शामिल करने और भारतीय भाषाओं में पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 8,000 से ज्यादा उच्च शिक्षण संस्थानों ने अपने पाठयक्रम में आईकेएस को अपनाना शुरू किया है।

राष्ट्रीय ऋण संरचना, जिसका विकास संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी), शिक्षा मंत्रालय (एमओई) और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के साथ किया गया है, एक व्यापक क्रेडिट संरचना है जिसमें प्राथमिक, स्कूल, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण शामिल है जिसमें सीखने के विभिन्न आयामों अर्थात् अकादमिक, व्यावसायिक कौशल और प्रासंगिक अनुभव और प्रवीणता/व्यावसायिक स्तरों सहित अनुभवात्मक शिक्षा का श्रेय शामिल है। इसमें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ), राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) और राष्ट्रीय पाठयचर्या फ्रेमवर्क (एनसीएफ) में निर्धारित योग्यता संरचना को शामिल किया गया है, जिससे लचीले पाठयक्रम के साथ व्यापकता-आधारित बहु-विषयक/ अंतर- अनुशासनात्मक, समग्र शिक्षा, विषयों का रचनात्मक संयोजन, अनेक मार्ग, समानता की स्थापना, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की सुविधा प्रदान करना शामिल है।

यह जानकारी राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

प्रेस की आजादी और कारोबार करने में सुगमता के एक नए युग की शुरुआत

शिमला। एक ऐतिहासिक निर्णय के तहत लोकसभा ने प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के औपनिवेशिक युग के कानून को निरस्त करते हुए प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023 पारित कर दिया। यह विधेयक पहले ही मानसून सत्र में राज्यसभा में पारित हो चुका है।

'प्रेस एवं पत्र-पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023' के नए कानून में किसी भी कार्यालय में गए बिना ही ऑनलाइन प्रणाली के जरिए पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल एवं समकालिक बना दिया गया है। इससे प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को इस प्रक्रिया को काफी तेज करने में मदद मिलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रकाशकों, विशेषकर छोटे और मध्यम प्रकाशकों को अपना प्रकाशन शुरू करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकाशकों को अब जिला मजिस्ट्रेटों या स्थानीय अधिकारियों के पास संबंधित घोषणा को प्रस्तुत करने और इस तरह की घोषणाओं को प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, प्रिंटिंग प्रेसों को भी इस तरह की कोई घोषणा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, इसके बजाये केवल एक सूचना ही पर्याप्त होगी। वर्तमान में इस पूरी प्रक्रिया में 8 चरण शामिल थे और इसमें काफी समय लगता था।

लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 'यह विधेयक, गुलामी की मानसिकता को खत्म करने एवं नए भारत के लिए नए कानून लाने की दिशा में मोदी सरकार के एक और कदम को प्रतिबिंबित करता है।' मंत्री ने कहा कि नए कानूनों के माध्यम से अपराध को समाप्त करना तथा व्यवसाय करने में आसानी व जीवन यापन में आसानी में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता रही है और तदनुसार, औपनिवेशिक युग के कानून को काफी हद तक अपराधमुक्त करने के प्रयास किए गए हैं। कुछ उल्लंघनों के लिए पहले की तरह अपराध सिद्ध करने के बजाये वित्तीय दंड का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, भारतीय प्रैस परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विश्वसनीय अपीलीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। व्यवसाय करने में आसानी के पहलू पर जोर देते हुए, ठाकुर ने कहा कि स्वामित्व पंजीकरण प्रक्रिया, जिसमें कभी-कभी 2-3 साल लग जाते थे, अब 60 दिनों में पूरी की जाएगी।

1867 का कानून ब्रिटिश राज की विरासत थी, जिसका उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों और पुस्तकों के मुद्रकों और प्रकाशकों पर पूर्ण नियंत्रण रखना था, साथ ही विभिन्न उल्लंघनों के लिए कारावास सहित भारी जुर्माना और दंड भी देना था। यह महसूस किया गया कि आज के स्वतंत्र प्रेस युग और मीडिया की स्वतंत्रता को बनाये रखने की सरकार की प्रतिबद्धता में, यह पुराना कानून वर्तमान मीडिया के परिदृश्य से पूरी तरह से मेल नहीं खाता है।

ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार

शिमला। पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये हैं:-

➪ भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया गया- आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक पहल

➪ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पोर्टल 16 फरवरी, 2023 को लॉन्च किया गया था। इस वेबसाइट में भारत में ग्रामीण पर्यटन स्थलों, भारत में ग्रामीण होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन के लिए सरकार और उद्योग की पहल आदि के बारे में जानकारी दी गई है।

➪ पर्यटन मंत्रालय ने केंद्रीय ग्रामीण पर्यटन नोडल एजेंसी के साथ साझेदारी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता आयोजित की। अंतिम मूल्यांकन में भारत के 35 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव सामने आये हैं।

➪ स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण सर्किट को एक विषयगत सर्किट के रूप में पहचाना गया था।

पर्यटन मंत्रालय ने केंद्रीय ग्रामीण पर्यटन नोडल एजेंसी के साथ साझेदारी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होमस्टे प्रतियोगिता 2024 शुरू की है। इस प्रतियोगिता की विशेषताएं यह हैं

➪ ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे के प्रचार, वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना।

➪ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।

➪ ग्रामीण पर्यटन गांवों और ग्रामीण होमस्टे की क्षमता बढ़ाना।

➪ ग्रामीण पर्यटन गांवों और ग्रामीण होमस्टे की पहचान और मान्यता।

प्रतियोगिता जिम्मेदार और टिकाऊ प्रथाओं के संबंध में ग्रामीण पर्यटन गांवों और ग्रामीण होमस्टे की सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और अन्य गांवों और ग्रामीण होमस्टे में उनकी प्रतिकृति पर केंद्रित है। यह प्रतियोगिता गांवों और होमस्टे को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का मंच उपलब्ध कराने में मदद करेगी।

यह प्रतियोगिता ग्रामीण स्तर पर बहुस्तरीय शासन को मजबूत करने के लिए केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करेगी।

यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में दी।

मुख्यमंत्री ने रैत में 5.36 करोड़ रुपए से बनने वाले बीडीओ कार्यालय भवन का किया शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रैत में 5.36 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले खंड विकास अधिकारी के कार्यालय भवन का शिलान्यास किया।

इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में तीन गारंटियां पूरी की हैं, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल में केवल मात्र प्रदेश की जनता को ठगने का ही कार्य किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में 1400 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की है। एक वर्ष में सरकारी क्षेत्र में ही 20 हजार से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कर्ज पर कर्ज लेती रही लेकिन लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मात्र एक वर्ष में 20 प्रतिशत तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कामयाब हुई है।

उन्होंने कहा कि विधवा महिलाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च उठाने के लिए भी राज्य सरकार एक योजना लाने जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कांगड़ा जिला में पहली बार 268 करोड़ रुपए की लागत से

औद्योगिक प्लांट स्थापित हो रहा है, जो एक वर्ष में बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने विधायक केवल सिंह पठानिया के आग्रह पर शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में रविदास भवन, ओ.बी.सी. भवन, गद्दी भवन तथा राजपूत भवन निर्माण का भी आश्वासन दिया।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि विधायक केवल पठानिया के प्रयासों से ही शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बीडीओ कार्यालय का नया भवन स्वीकृत हुआ। यह भवन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार होगा, ताकि स्थानीय निवासियों को इसका भरपूर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों का निर्माण कॉरपोरेट सैक्टर की तर्ज पर किया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों को कार्यालय में बेहतर कार्य परिवेश मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पंचायत घरों के निर्माण के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 1.14 करोड़ रुपए किया है। इसके साथ ही आपदा में लोगों को राहत प्रदान करने के लिए उनके विभाग ने 1085 करोड़ रुपए मनरेगा के माध्यम से स्वीकृत किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कंदरोड़ी में 268 करोड़ रूपये से बनने वाले पेप्सी प्लांट का किया शिलान्यास

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंदरोड़ी में 268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में इतने बड़े निवेश से लगने वाला यह पहला उद्योग है। इससे क्षेत्र में विकास को नई रफ्तार और आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस उद्योग के

माध्यम से दो हजार से अधिक युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने इंदौरा के औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए पर्याप्त बजट प्रदान करने का आश्वासन दिया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में निवेश के लिए एक उपयुक्त स्थल है। राज्य सरकार निवेशकों को अपने उद्योग स्थापित करने के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है और 10 हजार करोड़ रुपये की सरकारी कर्मचारियों की देनदारियां बकाया है। प्रदेश कभी भी कर्ज के सहारे नहीं चल सकता है, इसीलिए राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार दिन-रात प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के प्रत्येक निवासी पर एक लाख रुपए से अधिक का ऋण है, इसके बावजूद आगामी चार वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पिछले एक वर्ष में 20 प्रतिशत तक सुधार आया है और राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में राज्य की उद्योग नीति में भी बदलाव करने जा रही है, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांगड़ा जिला में कई बड़े उद्योग लगाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय में बढ़ौतरी के लिए अगले बजट में एक योजना का प्रावधान किया जाएगा।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आज का दिन कांगड़ा जिला के लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि यह प्लांट इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आशातीत बदलाव लायेगा। इस प्लांट को स्थापित करने के लिए सभी औपचारिकताएं तीन माह में पूरी की गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में हिमाचल प्रदेश में 10 हजार करोड़ रुपए का निवेश आया है। वर्तमान राज्य सरकार कांगड़ा जिला के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है तथा जिला को हिमाचल प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। प्रदेश सरकार कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए प्रयास कर रही है, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां आ सकें। युवाओं को रोज़गार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

विधायक मलेंद्र राजन ने इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में पेप्सी के मेगा प्लांट लगाने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे तथा कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इंदौरा विधानसभा क्षेत्र आर्थिक रूप से सम्पन्न होगा। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मलोट में उद्योगों की स्थापना के लिए 102 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे, जिससे यहां औद्योगिक निवेश आरंभ हुआ। उन्होंने कहा कि इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में किन्नू, संतरा आदि का अत्याधिक उत्पादन होता है तथा प्लांट की स्थापना से क्षेत्र के बागवानों को भी लाभ मिलेगा।

वरुण बेवरेजिज लिमिटेड के चेयरमैन रविकान्त जयपुरिया ने कहा कि यह पेप्सी प्लांट लगभग एक वर्ष में बनकर तैयार होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक उन्नति आएगी। उन्होंने कहा कि सीएसआर के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा और स्थानीय युवाओं के कौशल विकास के लिए भी कंपनी सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने उद्योग की स्थापना में राज्य सरकार की ओर से हरसंभव सहयोग के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त किया।

राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने क्रिसमस पर लोगों को बधाई दी

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

राज्यपाल ने कहा कि क्रिसमस ईसा मसीह के सत्य, प्रेम और भाईचारे के मार्ग पर निरन्तर चलने के गहन संदेश की याद दिलाता है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह त्योहार मानव जाति को सद्भाव से रहने और एक-दूसरे की देखभाल करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और महान शिक्षाएं आज कहीं अधिक प्रासंगिक हैं क्योंकि वे निःस्वार्थ सेवा, दया और मानवता को बढ़ावा देते हैं।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि क्रिसमस का पवित्र अवसर विश्वभर में शांति और प्रेम के संदेश को स्थापित करेगा और राज्य के लोगों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री ने 'दिव्य पूजा प्रणाली' का किया शुभारंभ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की पहली ऑनलाइन पूजा प्रणाली 'दिव्य पूजा प्रणाली' का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से भक्तों को घर बैठे ही ऑनलाइन पूजा की सुविधा उपलब्ध होगी। कांगड़ा जिला के माता ब्रजेश्वरी मंदिर, माता चामुंडा मंदिर और माता ज्वालामुखी मंदिर में वेबसाईट http://kangratemples.hp.gov.in. के माध्यम से वर्चुअल पूजा की सुविधा प्रदान की गई है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से श्रद्धालु किसी भी स्थान से ऑनलाइन पूजा और मंदिरों के लिए दर्शन पर्ची प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रणाली के माध्यम से भक्तों के लिए दान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। दान की गई राशि की ऑनलाइन रसीद की सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर विशेष अवसरों के लिए ई-पूजा बुकिंग, सराय बुकिंग, ऑनलाइन प्रसाद प्राप्त करने, ऑनलाइन दान करने के साथ-साथ मूर्तियों तथा पुस्तकों सहित धार्मिक वस्तुओं की खरीद की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। जिला प्रशासन ने भक्तों के घरद्वार तक इन वस्तुओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भारतीय डाक विभाग के साथ समन्वय किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर ट्रस्ट का वर्ष 2024 का कैलेंडर भी जारी किया।

कांगड़ा के उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने ऑनलाइन पूजा प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, कैबिनेट मंत्री यादविन्द्र गोमा, पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली, मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल और संजय अवस्थी, विधायक केवल सिंह पठानिया, संजय रतन, सुदर्शन बबलू, विनोद सुल्तानपुरी, आईडी लखनपाल, चैतन्य शर्मा, मलेंदर राजन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बीज विज्ञान कांग्रेस में नौणी विश्वविद्यालय ने जीते तीन पुरस्कार

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन के बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वैज्ञानिकों और छात्रों ने 'बदलती जलवायु के तहत गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्धता में नवाचार और चुनौतियां' विषय पर औरंगाबाद में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस-2023 में तीन पुरस्कार अपने नाम किये। यह कार्यक्रम वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, महाराष्ट्र और इंडियन सोसाइटी ऑफ सीड टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, वाराणसी के सहयोग से आयोजित किया गया।

बीज विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉ. रोहित वर्मा ने 'हिमाचल प्रदेश के मध्य-हिमालयी क्षेत्र में करेले में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन पर जिंक नैनोकण बीज उपचार का प्रभाव' पर लिखित शोध पत्र के लिए प्रथम पोस्टर प्रस्तुति पुरस्कार जीता। यह शोध प्रगति वर्मा, डॉ. रोहित वर्मा, डॉ.नरेंद्र भरत और डॉ.डी.के.मेहता द्वारा लिखा गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग के एक पीएचडी छात्र विनय ने इसी सत्र में अपने शोध पत्र 'हिमाचल प्रदेश की मध्य पहाड़ी परिस्थितियों में उपज, पौधों की वृद्धि, फूल और बीज में सुधार के लिए बीज प्राइमिंग उपचार और फोलियर एप्लिकेशन का प्रभाव' विषय पर पोस्टर प्रस्तुति में शोध पत्र के लिए दूसरा पुरस्कार जीता। इस शोध पत्र विनय, डॉ. बी.एस.दिल्टा, डॉ. राजेंद्र शर्मा, डॉ. रोहित वर्मा और डॉ. सपना कौशल द्वारा लिखित है।

इस कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के औदयानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय, थुनाग में कार्यरत सहायक प्रोफेसर डॉ. नेहा ठाकुर ने एक अन्य तकनीकी सत्र में पोस्टर प्रस्तुति में शोध पत्र के लिए तीसरा पुरस्कार जीता। डॉ. नेहा ठाकुर, डॉ. प्रियंका ठाकुर, डॉ. नरेंद्र भरत और राजीव कुमार द्वारा लिखित शोध पत्र 'कोदरा में रोपण के गुणों को प्रभावित करने वाले रासायनिक और प्राकृतिक फॉर्मूलेशन के साथ बुआई पूर्व बीज उपचार' विषय पर शोध पत्र के लिए तीसरा पुरस्कार जीता।

कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल, अनुसंधान निदेशक और बागवानी महाविद्यालय के डीन ने बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों और छात्रों को उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी।

भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की दो दिवसीय बैठक

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई जिसमें देश के सभी राज्यों के अध्यक्ष व

संगठन मंत्री राज्यों के प्रभारी व राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने भाग लिया।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बताया की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बैठक की अध्यक्षता की और मार्गदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब का कल्याण, गरीब का विकास ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और भारत के गरीबों का संपूर्ण विकास करते हुए हमें राष्ट्र का विकास करना है यह लक्ष्य निर्धारित किया। मोदी जी ने कहा कि हमें देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ना है और यह गति अब नहीं रुकनी चाहिए । अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल राष्ट्र निर्माण के 10 साल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें 2004 से 2014 के कांग्रेस के शासन और 2014 से 2024 के मोदी शासन की तुलना करनी चाहिए। मोदी सरकार के कारण जहां देश की सीमाएं सुरक्षित हुई वही आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई। जहां विश्व में भारत की ख्याति मजबूत हुई वही देश का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हुआ मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश ने आर्थिक प्रगति की वही किसान को समृद्ध करने के लिए प्रत्येक किसान को आर्थिक मदद पहुंचाई और उसके उत्पाद का दाम अधिक मिले ऐसी व्यवस्था की गई। गरीब कल्याण के, आर्थिक विकास के, देश की सुरक्षा के, आधारभूत ढांचे के विकास के, भ्रष्टाचार मुक्त शासन के यह साढ़े वर्ष देश के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे इसलिए मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना देश की जरूरत है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जे पी नड्डा ने कहा कि देश के चार वर्ग गरीब, महिला, युवा व किसान इनका विकास करते हुए देश को दुनिया की महाशक्ति बनाना है इसके लिए भाजपा पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। तीन राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत ने देश की जनता मोदी जी के साथ है यह स्पष्ट कर दिया है । नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं का आवाहन करते हुए कहा की आओ हम सब मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगातार काम करें।

ढल्ली टनल का श्रेय लेने का प्रयास कर रही कांग्रेस:कश्यप

शिमला/शैल। भाजपा के पूर्व

अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने कहा ढल्ली टनल के निर्माण का पैसा केंद्र से आया है जिसका श्रेय कांग्रेस लेने का प्रयास कर रही है। यह जग जाहिर है की ढल्ली टनल को स्वीकृत भाजपा सरकार ने किया, इसका करोड़ों रुपए भी भाजपा सरकार ही लायी। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यह टनल बनी है। इसकी पूरी प्लानिंग और डीपीआर भी भाजपा सरकार के दौरान ही तैयार की गयी है पर आज जब इसकी शुरुआत होनी है तो कांग्रेस केवल मात्र इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा की यह सरकार तो केवल ऋण लेना जानती है, कांग्रेस सरकार केवल ऋण लेकर घी पीना जानती है।

इस टनल के साथ एक फुटपाथ भी बनना था जो की साथ लगती बस्ती को जाना था पर उस फुटपाथ को भी नहीं बनाया गया जिससे जनता परेशान है। जब से कांग्रेस की सरकार सत्ता में आयी है तब से केवल पटीका लगाने का कार्य कर रही है इससे उनको कोई लाभ नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि कम से कम कांग्रेस के नेताओं को यह मान लेना चाहिए कि ऐसे निर्माण कार्यों के पीछे भाजपा की दृढ़ इच्छा शक्ति थी।

अटल जयंती की बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना:कटवाल

शिमला/शैल। भाजपा प्रदेश मुख्यालय दीपकामल चक्कर शिमला में प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी वाजपेई की जयंती और सुशासन दिवस के अवसर पर पुष्पांजलि का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर काव्यांजलि और पुष्पांजलि का कार्यक्रम

भी हुआ।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा की सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से 2014 में भारत की जीडीपी 98 लाख करोड़ थी और अब 2023 में 159.7 लाख करोड़ रही। भारत का पूंजीगत व्यय 2014 में 3.92 लाख करोड़ था और 2023 में यह 10.9 लाख करोड़ पहुंच गया है। देश का कृषि बजट 2014 में 21900 करोड़ से बढ़ कर, 2023 में 1.25 लाख करोड़ हो गया है। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित, फॉरेक्स रिजर्व मई 2014 में 313 अरब डॉलर थी जो की जून 2023 में 600 अरब डॉलर पहुंच गई है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो की 2014 में 45 अरब डॉलर था अब 2022 तक 84.8 अरब डॉलर पहुंच गया है। भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014 में 86454 रूपये थी और 2022 में 1.50 लाख पहुंच गई। 2014 और 2023 की तुलना में देश की गरीबी दर 22% से कम हो कर 10% तक आ गयी। भारतीय अर्थव्यवस्था की दुनिया में रैंक भारत की अर्थव्यवस्था 2014 में 10वे नंबर पर थी और 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ते हुए 5वें स्थान पर पहुंच गई है।

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव कटवाल ने कहा की 2002 में अटल जी ने डेयरी सैक्टर को पूरी तरह से डी-लाइसेंस कर दिया। इसके बाद, निजी क्षेत्र ने बाद के वर्षों में अपनी प्रसंस्करण क्षमता को सहकारी समितियों की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके कारण मोदी सरकार के नेतृत्व में 2018 तक भारत दुनिया का शीर्ष दूध उत्पादक बन गया। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता जो 2014 में 303 ग्राम थी, 2022-2023 में बढ़कर 459 ग्राम हो गई। 2003 के मॉडल एक्ट के माध्यम से कृषि-मार्केटिंग में अटल जी द्वारा शुरू किए गए सुशासन सुधारों को मोदी सरकार ने तेजी से बढ़ाया। आज भारत की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 200 मीट्रिक टन है, जो 2014 में सिर्फ 12 मीट्रिक टन थी। अटल जी के सर्व शिक्षा अभियान से प्रेरणा लेते हुये 'भारत में दस लाख बच्चों को नियोटेरिक इनोवेटर्स के रूप में तैयार करने' के दृष्टिकोण के साथ, हमारे देश भर के स्कूलों में कुल 10,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालायें स्थापित की गई हैं, जो जिज्ञासा, रचनात्मकता और कौशल को बढ़ावा देती हैं।

कांग्रेस सरकार के गले पड़ गई चुनावी गारंटियां:जयराम ठाकुर

विपक्ष का काम है सरकार की त्रुटियों को इंगित करना

विधानसभा में असहज दिखी सरकार

शिमला/शैल। नेता प्रतिपक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि चुनावी गारंटियां प्रदेश की कांग्रेस सरकार के गले पड़ गई हैं। झूठी गारंटियां देने वाले इनके छत्तीसगढ़

और राजस्थान के नेता तो घर बैठ गये हैं लेकिन हिमाचल की जनता को वोट बैंक की खातिर धोखा देकर इन्होंने हजारों करोड़ के बोझ तले दबने को विवश कर दिया है। एक साल में जो सरकार 14 हज़ार करोड़ रुपए का ऋण ले चुकी है वो आगे पांच वर्ष कितना बोझ हिमाचल पर डालने जा रही है उसका अभी से अनुमान लगाया जा सकता है। भाजपा अब तक तक चुप नहीं बैठेगी जब तक ये सरकार अपनी दी इन गारंटियो को पूरा नहीं करती। भाजपा आगे भी सदन के अंदर और बाहर कांग्रेस को इसकी याद दिलाती रहेगी।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधान सभा के शीतकालीन सत्र में सरकार से इन झूठी गारंटियों का जवाब देते नहीं बन पा रहा था। पूरी सरकार सत्र में असहज दिखी। भाजपा विधायक दल और पार्टी ने तय किया था कि सरकार को इनकी चुनावों में दी गारंटियां विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह याद दिलाई जाये जो इन्होंने एक वर्ष पूर्व सत्ता में आने से पहले जनता को दी थी। एक वर्ष बीत गया लेकिन अभी भी कोई गारंटी धरातल पर नहीं उतरी है। सबसे बड़ा छल इन्होंने महिलाओं, बेरोजगारों और किसानों से किया है। कहा था पहली जनवरी से महिलाओं के खाते में 1500 रुपए हर माह आयेंगे लेकिन एक साल इंतजार करते निकल गया। कहा था पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी क्षेत्र में पक्की नौकरी वाला रोजगार निकालेंगे लेकिन दूसरा वर्ष शुरू हो गया है। कहा था दूध 100 रुपए लीटर खरीदेंगे पर ये वायदा भी सिर्फ चुनावी निकला। उन्होंने कहा कि यह वर्तमान सरकार का धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के रूप में दूसरा सत्र है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र का गहना है और इसको हमें अच्छी स्पिरिट में आगे बढ़ाना चाहिए व प्रदेश के विकास में सभी को यथा-संभव अपना योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की तकमियों को इंगित करने का है, चाहे वह सरकार को पसंद आये या न आये लेकिन यह विपक्ष की लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बाकी राज्यों के मुकाबले हिमाचल प्रदेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह बहुत स्वस्थ और बेहतर है। उन्होंने पक्ष तथा विपक्ष के सदस्यों का भी अपने क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को इस सदन में संजीदगी से उठाने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि सदन में विभिन्न विषयों पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच में नोकझोंक चलती रहती है लेकिन प्रदेशहित के सुझावों पर सरकार द्वारा अमल भी किया जाता है।

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोकसभा के बाहर संसद से निलंबित सांसदों द्वारा नुक्कड़ सभा में उपराष्ट्रपति के उपहास को संवैधानिक पदों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि बेशर्मी की हद देखिए कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी इस घटना का स्वयं वीडियो बना रहे थे और हंसते हुए विपक्षी सांसदों को ऐसा करने के लिए उकसा रहे थे जो बेहद हैरानी की बात है।

स्टांप डयूटी में दस गुना बढ़ौत्तरी करना गलत निर्णय:चेतन बरागटा

शिमला/शैल। हिमाचल सरकार ने भूमि खरीद पर स्टांप डयूटी में संशोधन कर, स्टांप ड्यूटी को दस गुना बढ़ाकर प्रदेश की जनता पर

अतिरिक्त बोझ डालने का कार्य किया है। यह बात प्रदेश भाजपा प्रवक्ता चेतन सिंह बरागटा ने कही, उन्होंने कहा जबसे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है,इस सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर बिना सोच समझ के गलत निर्णय लिये है।

गौरतलब है कि अब पुरुषों को 50 लाख पर छह प्रतिशत और इससे अधिक की खरीद पर आठ प्रतिशत स्टांप डयूटी चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा जनरल पावर आफ अटार्नी (जीपीए) शुल्क को 100 से 1000, 150 से 1500 और 200 से 2000 रुपये किया गया है। न्यूनतम 1000 पर 5000 रुपये स्टांप ड्यूटी किया गया है। 100 की जगह 200 रुपये जीपीए करना तो सही होता, सरकार पांच प्रतिशत की वृद्धि करती तो उसे उचित माना जाता, लेकिन 100 को सीधे 1000 रुपये करना सही नहीं है। स्टांप ड्यूटी में दस गुणा वृद्धि करना अचंभित करने वाला निर्णय है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टांप ड्यूटी वृद्धि चुकाने में लोग असमर्थ होंगे।

चेतन बरागटा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के गलत निर्णयों के कारण जनता का सरकार से मोह भंग हो गया है। सरकार द्वारा कि स्टांप ड्यूटी वृद्धि को जनता कभी स्वीकार नही कर सकती।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

क्या सरकार और संगठन के खेमों में बंटी पार्टी को एकजुट कर पायेगी हाईकमान

> भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं की चुप्पी सवालों में
>
> मंत्रियों को विभागों का आवंटन न हो पाना सरकार के अंदर का आईना

शिमला/शैल। कांग्रेस हाईकमान ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में मिली अप्रत्याशित हार के बाद राष्ट्रीय संगठन में एक बड़ा फेरबदल किया है। इसी के साथ इन राज्यों में कांग्रेस की हार का एक बड़ा कारण हिमाचल की कांग्रेस की परफॉरमैन्स भी माना गया है। क्योंकि इन राज्यों में कांग्रेस ने जो भी चुनावी वायदे किये उनकी विश्वसनीयता पर यहां की परफॉरमैन्स से स्वतः ही प्रश्न चिन्ह लग गया। भाजपा ने अपने हिमाचल के नेताओं के माध्यम से इसे मुद्दा बनाया और उसका जवाब देने के लिये हिमाचल का कोई भी नेता वहां पर उपलब्ध नहीं था। सूत्रों के मुताबिक उस वस्तुस्थिति का कांग्रेस हाईकमान ने कड़ा संज्ञान लिया है। इसीलिये प्रदेश सरकार द्वारा मनाये गये एक साला जश्न के समारोह में हाईकमान का एक भी नेता शामिल नहीं हुआ। यहां तक की प्रियंका गांधी शिमला में मौजूद होने के बाद भी धर्मशाला नहीं गयी। इस समारोह के बाद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमण्डल में यादविंदर गोमा और राजेश धर्माणी को मंत्रिमण्डल में शामिल किया लेकिन उन्हें अभी तक विभाग नहीं दिये जा सके हैं। इससे अन्दाजा लग जाता है कि प्रदेश कैसे चल रहा है। फिर बहुत पहले कांग्रेस हाईकमान द्वारा लोकसभा चुनावों को लेकर करवाया गया सर्वे भी वायरल हो चुका है और उसके मुताबिक हिमाचल में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद प्रदेश की चारों सीटें पार्टी हार रही है। इस परिदृश्य में हो रही दिल्ली की बैठक कितनी अहम होगी इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। विधानसभा के धर्मशाला में हुये शीत सत्र में भाजपा सदन के भीतर और बाहर सरकार पर गारंटीयों, कर्ज और रोजगार के मुद्दों पर लगातार आक्रामक रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर एक वर्ष के कार्यकाल में ही 14000 करोड़ का कर्ज लेने का बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा का यह आरोप कर्ज को लेकर सदन में पूछे गये सवाल पर आये जवाब से प्रमाणित भी हो जाता है। इस जबाब के मुताबिक 01-01-2023 से लेकर 01-11-2023 तक सरकार 12485.85 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। इस कर्ज में नवम्बर और दिसम्बर में लिये गये कर्ज का आंकड़ा जोड़ने से यह कर्ज का आंकड़ा चौदह हजार करोड़ हो जाता है। इसी तरह रोजगार को लेकर जब भाजपा ने अपने प्रदर्शन में डिग्रीयां जलाई थी तब मुख्यमंत्री ने एक पत्रकार वार्ता में रोजगार को लेकर लम्बे चौड़े आंकड़े मीडिया में परोसे थे। स्वभाविक है कि प्रशासन ने जो फीडबैक मुख्यमन्त्री को दिया होगा उसके मुताबिक उन्होंने ब्यान दे दिया। लेकिन रोजगार पर भी विधानसभा के इसी सत्र में सवाल पूछा गया था कि 01-02-2022 से 15-11-2023 तक सरकार के विभागों, निगमों और बोर्ड में किसानों को स्थाई रोजगार दिया गया। इसके जवाब में कहा गया है कि सूचना अभी एकत्रित की जा रही है। ऐसे कई जवाब हैं जो सरकार के दावों का सच बाहर रख रहे हैं। सरकार के दावे मीडिया के लिये तो खबर हो जाते हैं लेकिन भुक्तभोगी जनता पर उसका प्रभाव प्रतिकूल पड़ता है। सरकार और संगठन में कैसा तालमेल है इसको लेकर न केवल प्रतिभा सिंह बल्कि पूर्व अध्यक्ष कुलदीप राठौर, कॉल सिंह ठाकुर और विप्लव ठाकुर जैसे नेता इसका खुलासा कर चुके हैं। सरकार बनने के बाद संगठन के साथ तालमेल बिठाना और बेहतर बनाना सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। सरकार की ताजपोशियों में क्षेत्रीय संतुलन बनाना भी सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन संयोगवश इस समय सरकार स्व. वीरभद्र सिंह और सुक्खू खेमे में बंटी पड़ी है। क्योंकि सुक्खू ने उन कार्यकर्ताओं को अधिमान देने के प्रयास किये हैं जो लम्बे अरसे से नजरअन्दाज चल रहे थे। लेकिन इसके साथ जब सरकार की परफॉरमैन्स भी प्रश्नित हो गई तो एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। क्योंकि आज भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ दर्जनों मुद्दे होने के बावजूद कोई भी नेता उन पर मुंह खोलने को तैयार नहीं है।

किसी के भी खिलाफ स्थायी

........पृष्ठ 1 का शेष

में इस मानहानि के मामले के लंबित होते हुये रचना गुप्ता उच्च न्यायालय की एकल पीठ से देवाशीष भट्टाचार्य के खिलाफ एक गैग ऑर्डर पाने में सफल हो गयी थी। देवाशीष ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी और 12-12-2023 को यह संशोधित फैसला आ गया जिसमें गैग ऑर्डर को निरस्त करते हुये यह शर्त लगायी गयी की लेखन असत्य और अप्रमाणित नहीं होना चाहिये। जब यह गैग आदेश आया था तब इससे यह संदेश गया था कि प्रभावशाली लोगों के खिलाफ आर.टी.आई. सूचनाओं के आधार पर कलम उठाना कठिन है। लेकिन संशोधित आदेश से स्पष्ट हो गया कि कानून के आगे कोई भी प्रभावशाली नहीं है। इस आदेश से प्रशासन को भी यह संदेश गया कि आर.टी.आई. के माध्यम या अन्य प्रमाणिक दस्तावेजों के माध्यम से सार्वजनिक हुई जानकारीयों को नजर अन्दाज करना सही नहीं होगा।

यह रहा उच्च न्यायालय का आदेश

This appeal has been preferred by the appellant defendant against interim injunction order dated 03.01.2020, passed in OMP No.574 of 2019 in COMS No.20 of 2019, titled as Dr.Rachna Gupta vs.Dev Ashish Bhattacharya The operative portion of the impugned order is as under:-

" In these circumstances taking into consideration the above mentioned circumstances, the application is allowed and the non - applicant (defendant) is restrained from posting or publishing any statement of any nature, against the applicant, her husband and her family members on facebook or on any other social media, including print or electronic media, till the disposal of the main suit Accordingly, the application is disposed of."

2. The main ground for assailing the impugned order is that appellant-defendant has been restrained from posting or publishing "any statement of any nature" against the respondent- plaintiff, her husband and her family members. It has been contended that such blanket gag order is not permissible under law.

3. The passing of aforesaid injunction order against the appellant-defendant has been justified by learned counsel for the respondent-plaintiff by referring documents filed with the plaint as well as with application CMP No.18474 of 2023 in this appeal.

4. Taking into consideration averments in the pleadings, documents placed on record, case law referred in impugned order and submissions made by learned counsel for the parties and also balancing the rights and reasonable restriction with reference to Article 19 of the Constitution of India, interim injunction order is modified as under:- "Taking into consideration the facts and circumstances, the non- applicant (defendant) is restrained from posting or publishing any defamatory, scandalous, untrue and/or unverified statement, directly or indirectly, against the applicant/plaintiff, her husband and her family members on facebook or on any other social media, including print or electronic media, till the disposal of the main suit."

5. Appeal is disposed of in aforesaid terms, so also pending application(s), if any